



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 414]
No. 414]

नई दिल्ली, रविवार, सितम्बर 7, 1986/भाद्रा 16, 1908
NEW DELHI, SUNDAY, SEPTEMBER 7, 1986/BHADRA 16, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1986

उद्घोषणा

सा.का.नि. 1061 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्न-
लिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनायें प्रकाशित की जा रही है:—

यस: मुझे, भारत के राष्ट्रपति, खेल विह. को जम्मू व कश्मीर राज्य
के राज्यपाल ने एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और इस रिपोर्ट तथा मुझे
प्राप्त अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया
है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें उस राज्य का शासन
भारत के संविधान, जैसा कि वह उस राज्य पर लागू है (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'संविधान' कहा गया है) और जम्मू व कश्मीर के संविधान
(जिसे इसमें शर्तक पश्चात् 'राज्य संविधान' कहा गया है) के उपबंधों
के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।

अतः, अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
तथा उन निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग
करते हुए एतद्वारा उद्घोषणा करता हूँ कि मैं—

- (क) संविधान और राज्य संविधान के अधीन उक्त राज्य की सरकार
के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित अथवा
उसके द्वारा प्रयोज्य सभी शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति के
रूप में स्वयं संभालता हूँ;

- (ख) उद्घोषित करता हूँ कि उक्त राज्य के विधान मंडल की
शक्तियाँ संसद द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन
प्रयोज्य होंगी; और

- (ग) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध करता हूँ
जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए
मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात्:—

- (i) पूर्वोक्त के अनुसार, इस उद्घोषणा के अन्तर्गत (क) के
आधार पर मेरे द्वारा संभाले गए कृत्यों तथा शक्तियों
का प्रयोग करने में मेरे लिए, भारत के राष्ट्रपति के
रूप में उस सीमा तक जित तक मैं ठीक समझूँ,
उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना
विधिपूर्ण होगा;

- (ii) संविधान के तथा राज्य संविधान के निम्नलिखित
उपबंधों के प्रवर्तन को एतद्वारा निलम्बित किया
जाता है, अर्थात्:—

संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रथम परन्तुक का उक्त
भाग जिनके का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधान-
मंडल के प्रति निदेश से है, और उस अनुच्छेद का
दूसरा परन्तुक;

संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष किए प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाने से है;

राज्य संविधान की धाराएं 35 से 41 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) धारा 45 का उतना भाग जितने का संबंध राज्य सरकार के गंत्रियों के बीच कार्य के बंटवारे से है, धारा 44, धारा 53 की उप-धारा (1) और उपधारा (2) का खंड (क), धाराएं 54, 55, 56 तथा 57 धारा 58 के खंड (ख) और (ग) और उसका पहला परन्तुक, धारा 59, धारा 60, धारा 61 की उपधारा (2), जहां तक उसका संबंध धारा 58 के खंड (ग) और पहले परन्तुक से तथा धारा 60 से है;

धाराएं 65, 66, 67, 71 और 72, धाराएं 74, 75 और 76, धारा 77 की उपधारा (3) तथा (4), धाराएं 85 से 88 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) और धारा 137 का उतना भाग जितने का संबंध जापन सहित रिपोर्ट के राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाने से है;

- (iii) संविधान में, और राज्य के संविधान में, राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उक्त राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जाएगा, और संविधान में तथा राज्य के संविधान में राज्य के विधानमंडल या उसके सदस्यों के प्रति, यथास्थिति, किसी निदेश का, जहां तक उसका सम्बन्ध उसके कृत्यों और शक्तियों से है, अर्थ, जब तक संबंध द्वारा अन्यथा अव्यक्त न हो, संसद के प्रति निदेश लगाया जाएगा, और विधिगत तथा राज्य के संविधान की धारा 91 में राज्यपाल के प्रति और राज्य के विधानमंडल अथवा उसके सदस्यों के प्रति निदेश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति के प्रति और संसद या उसके सदस्यों के प्रति निदेश लगाया जाएगा;

परन्तु इसमें की कोई बात राज्य संविधान की धारा 26 की उपधारा (1), धाराएं 27 से 31 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), धारा 122, धारा 143 और दूसरी अनुसूची के पैरा 1 से 8 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को इस खंड के उपखंड (i) के अधीन, उस सीमा तक जहां तक वह ठीक समझे, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम के कार्य करने से निवारित करेगी;

- (iv) संविधान में, या राज्य संविधान में राज्य के विधानमंडल के या उसके द्वारा अर्थात् राष्ट्रधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदेश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह अधिनियमों या विधियों को भी समाविष्ट करता है जो इस उद्घोषणा के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड (क) से निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं, और जम्मू व काश्मीर साधारण खंड अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्या 20) और साधारण खंड अधिनियम 1897 (1897 का 10) का उतना भाग जितना राज्य की विधियों पर लागू होता है, ऐसे किसी अधिनियम

या विधि के बारे में इस प्रकार प्रभावी होगा मानो यह उस राज्य के विधानमंडल का अधिनियम हो।

नई दिल्ली,

दिनांक 7 सितम्बर, 1986

जैल सिंह,

राष्ट्रपति

[क्र. सं. 11011/4/86-क]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 7th September, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 1061(E).—The following Proclamation by the President is published for general information :

Whereas, I, Zail Singh, President of India, have received a report from the Governor of the State of Jammu and Kashmir and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India, as applicable to that State (hereinafter referred to as "the Constitution") and of the Constitution of Jammu and Kashmir (hereinafter referred to as "the State Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I —

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution and the State Constitution;
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
- (c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely :—
 - (i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;
 - (ii) the operation of the following provisions of the Constitution and of the State Constitution is hereby suspended, namely :—

so much of the first proviso to article 3 of the Constitution as relates to the reference by the President to the Legislature of the State and the second proviso to that article;

so much of clause (2) of article 151 of the Constitution as relates to the laying before the Legislature of the State of

the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

sections 35 to 41 (both inclusive), so much of section 43 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State, section 44, sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 53, sections 54, 55, 56 and 57, clauses (b) and (c) of section 58 and the first proviso thereto, section 59, section 60, sub-section (2) of section 61 so far as it relates to clause (c) of, and the first proviso to, section 58 and to section 60, sections 65, 66, 67, 71 and 72; sections 74, 75 and 76 sub-sections (3) and (4) of section 77, sections 85 to 88 (both inclusive) and so much of section 137 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State of the State Constitution;

- (iii) any reference in the Constitution and the State Constitution to the Governor shall, in relation to the said State, be construed as a reference to the President, and any reference in the Constitution and the State Constitution to the Legislature of the State or the House thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in section 91 of the State Constitution to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively :

Provided that nothing herein shall affect the provisions of sub-section (1) of section 26, sections 27 to 31 (both inclusive), section 122, section 143 and paragraph 1 to 8 (both inclusive) of the Second Schedule to the State Constitution or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

- (iv) any reference in the Constitution or in the State Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Jammu and Kashmir General Clauses Act, 1977 (Act No. XX of 1977) and so much of the General Clauses Act, 1897 10 of 1897 as applies to State laws, shall

have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

New Delhi.

The 7th September, 1986.

ZAIL SINGH
PRESIDENT

[F. No. 11011/4/86-K]

प्रादेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1986

सा.का.नि. 1062(ग).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित प्रादेश सर्वसाधारण के लिये प्रकाशित किया जा रहा है:—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज सितम्बर, 1986 के सातवें दिन जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) के उप-खंड (i) के अनुसरण में, मैं पृष्ठद्वारा निर्देश देता हूँ कि जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार के सभी कृत्य तथा संविधान और जम्मू व कश्मीर के संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोज्य सभी शक्तियाँ, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खंड (क) के अधार पर स्वयं संभाल लिया है, राष्ट्रपति के प्रवीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोज्य होंगी।

नई दिल्ली,

दिनांक 7 सितम्बर, 1986

जैल सिंह

राष्ट्रपति

[फा. सं. 11011/4/86-के]

सी.जी. सोमिया, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th September, 1986

G.S.R. 1062(E).—The following Order by the President is published for general information :—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the Seventh day of September, 1986, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Jammu and Kashmir and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution and the Constitution of Jammu and Kashmir or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi:

The 7th September, 1986

ZAIL SINGH
PRESIDENT

[F. No. 11011/4/86-K]

C. G. SOMIAH, Home Secy.

